नव भारत भोपाल
26 MAY 2015

अभियान | स्वच्छ भारत अभियान को मध्यप्रदेश ने गंभीरता से लिया

केन्द्र के हमकदम मध्यप्रदेश : शिवराज सिंह चौहान

लगातार विजय से जिम्मेदारियाँ और उन्हें पूरा करने की चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाती हैं. दिसम्बर 2013 में जब तीसरी बार जीतकर मैं मुख्यमंत्री बना, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ. इसके बाद 6 माह के पश्चात माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व केन्द्र में हमारी सरकार बनी. उनकी सोच, दिशा और गतिशीलता के अनुरूप प्रदेश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना और भी बड़ी चुनौती बन गई. प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार के बाद हमने मध्यप्रदेश को आधुनिक बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया है. कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश आज देश का सिरमौर है. उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत गतिशीलता आयी है.

प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिये जो नीतिगत पहल की उन्हें हमने मध्यप्रदेश में पूरी तत्परता से लागू करते हुए आधुनिक मध्यप्रदेश गढ़ने की ओर ठोस कदम बढ़ाये. वित्तीय समावेशन के लिये लागू प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लक्ष्य पूरा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है. अब प्रदेश में हर परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता खुल गया है. अब शासकीय योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफेट ट्रान्सफर के काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके पहले भी मध्यप्रदेश मनरेगा की मजदूरी और हितग्राही योजनाओं की हितलाभ राशि लाभांवितों के खाते में सीधे जमा करवा रहा था. इसी माह की 9 तारीख से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना लागू की है. देश की बड़ी आबादी को सामाजिक सुरक्षा देने वाली इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को दिलाने के लिये मध्यप्रदेश में अभियान चालाकर कार्य किया जा रहा है. अभियान की देख-रेख मंत्रि-परिषद के सदस्य कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को मध्यप्रदेश में पूरी गंभीरता से लिया गया है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता के लिये अलग-अलग रणनीति बनायी गई है. अक्टूबर 2015 से पहले प्रदेश के सभी स्कूलों में शौचालय बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा. मेक इन इंडिया की तर्ज पर 'मेक इन मध्यप्रदेश' और 'डिजिटल मध्यप्रदेश' बनाने की पहल भी की गई है.

मेक इन मध्यप्रदेश के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाये जाने के बाद हमने देश में सबसे पहले रक्षा उत्पादन उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई है. हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एण्ड डिजायनिंग पॉलिसी भी बनायी है. सेमीकण्डक्टर फेब पॉलिसी बनाने वाला भी मध्यप्रदेश पहला राज्य है. भोपाल और जबलपुर के आईटी पार्क में इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट शुरू की जा रही हैं. देश में पहली बार माइक्रो चिप के निर्माण का गौरव मध्यप्रदेश को प्राप्त होगा.

प्रदेश में उद्योग एवं व्यवसाय को और अधिक सुगम बनाने के लिये हमने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में सुधार के लिये ठोस कदम उठाये हैं. इस संबंध में नियम-कानून और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है. अनावश्यक अनुमतियों को समाप्त किया जा रहा है. उद्योगों के लिये हमने सिंगल डोर पॉलिसी लागू की है. प्रक्रियाओं को सरल करते हुए श्रम कानूनों में भी आवश्यक सुधार किये गये हैं. वालियंटरी कम्पलाइंस स्कीम लागू की गई है, जिसमें इकाइयों को पाँच वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण की सुविधा दी गई है. सत्रह केन्द्रीय श्रम कानून में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं. इकाइयों को 61 के स्थान पर केवल एक रजिस्टर रखने की सुविधा दी गई है. अब उन्हें 13 की जगह सिर्फ 2 वार्षिक विवरणियाँ रखने की सुविधा भी दी गई है. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में सुधार के लिये 150 मुद्दे चिन्हित किये गये हैं.

प्रदेश में सुशासन की अवधारणा को मूर्तरूप देने में हमने सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया है. नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिये सीएम हेल्पलाइन शुरू की गई है. इसके जरिये अभी तक लाखों जन-शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है. एक बड़ी पहल के रूप में सभी 23 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत को नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के जरिये ब्राड बेंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा रही है.

सरकारी दफ्तरों में लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिये मैंने बहुत प्रभावी कदम उठाये हैं. अनेक कामों के लिये दस्तावेज नोटरी करवाने और विद्यार्थियों को दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाने की व्यवस्था समाप्त कर दी है. उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई है. अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, छात्रवृत्ति, बिजली कनेक्शन, निर्माण श्रमिक पंजीयन आदि के कार्यों में शपथ पत्र लगाने की जरूरत नहीं है. इसके लिये अब न स्टॉम्प खरीदने की जरूरत और न नोटरी की. मेरी सरकार ने जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था भी की है. सामाजिक क्षेत्र पर भी हमने बराबर ध्यान दिया है. प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 279 से घटकर 221 तथा शिशु मृत्यु दर 59 से घटकर 54 हो गई है. शिशु मृत्यु दर में यह गिरावट देश में सबसे अधिक है. शिक्षा के क्षेत्र में हम विशेष रूप से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिये यह वर्ष शैक्षणिक गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. प्रदेश में उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान खुल रहे हैं.

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिये जो नीतिगत पहल की उन्हें हमने मध्यप्रदेश में पूरी तत्परता से लागू करते हुए आधुनिक मध्यप्रदेश गढ़ने की ओर ठोस कदम बढ़ाये. वित्तीय समावेशन के लिये लागू प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लक्ष्य पूरा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है.